ग्रीवेन्स कमेटी में लिए गए दुष्यंत के फैसले को साजिश कर पलटा

श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल मामले की लिखित कार्यवाही भी बदली, जबकि बैठक का वीडियो मौजूद

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल मामले में राजनीतिक रसूख रखने वालों के हस्तक्षेप पर न सिर्फ ग्रीवेन्स कमेटी के एजेंडा का विषय बदल दिया गया, बल्कि ग्रीवेन्स कमेटी की बैठक में अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के फैसले को ही पलटने की साजिश रची गई। इसकी आड़ में अवैध तरीके से अस्पताल में ओपीडी भी शुरू कर दी गई है, जहां गलत तरीके से टेस्ट शुरू हो गए हैं। जिला रजिस्ट्रार सोसाइटीज द्वारा नियुक्त प्रशासक लौट कर नहीं आया, जबकि कुछ लोग अवैध रूप से अस्पताल में प्रवेश कर वहां दिशा निर्देश दे रहे हैं।

ग्रीवेन्स कमेटी की एजेंडा बदला

श्रीराम चैरिटेबल सोसाइटी के उपाध्यक्ष विशाल भाटिया ने जिला प्रशासन से अस्पताल में हुई अवैध गतिविधियों को लेकर शिकायत की थी। उस शिकायत को ग्रीवेन्स कमेटी की 28 जून को हुई बैठक में शामिल किया गया। विशाल भाटिया ने आरोप लगाया था कि कंवल खत्री गुट किस तरह कोविड की आड़ लेकर अस्पताल में घुसा। किस तरह सोसाइटी के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। अस्पताल की चाबी धर्मगुरु के पास होने के बावजूद डुप्लीकेट चाबियों से कैश बॉक्स, लॉकर्स आदि के ताले खोले गए। बैंक में रखे एफडी के पैसे को लुटाया गया, जिसके पीछे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। चूंकि फरीदाबाद में कोरोना खत्म हो चुका है तो अस्पताल को फिर से सील करने और इसे नगर निगम के

कब्जे में दिया जाए। क्योंकि नगर निगम ने इसे अपनी संपत्ति मानते हुए सील लगाई थी। ग्रीवेन्स कमेटी के सदस्यों को 28 जून का जो एजेंडा भेजा गया था, उसमें यही सवाल शामिल था। इस पर डिप्टी सीएम ने एसडीएम बडखल से कहा था कि दोनों गुटों के पांच-पांच लोगों की कमेटी बनाकर अस्पताल चलाया जाए और पूरे प्रकरण की जांच एसडीएम करके उन्हें रिपोर्ट सौंपे। दोनों पक्ष इससे संतुष्ट हो गए।

हालांकि ग्रीवेन्स कमेटी में लिए गए फैसले की लिखित कार्यवाही रिपोर्ट 10 से 15 दिनों में सदस्यों को भेज दी जाती है। लेकिन 28 जून की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट इसी हफ्ते सदस्यों को जारी की गई है। इसमें ग्रीवेन्स कमेटी के एजेंडा का सवाल विशाल भाटिया के नाम से बदल दिया गया है। लेकिन उनके जिस सवाल को इस कार्यवाही रिपोर्ट में लिखा गया, उसका बड़ा हिस्सा विशाल भाटिया के सवाल में शामिल नहीं था। उसे पूरी तरह बदल दिया गया है।

सबसे आपत्तिजनक

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मौके पर घोषणा की थी दोनों गुटों के लोगों की पांच-पांच लोगों की कमेटी बना दी जाए, जिसके मुखिया एसडीएम बडखल होंगे। दुष्यंत की इस घोषणा के वीडिया सबूत मौजूद हैं लेकिन उस दिन के बैठक की जो कार्यवाही रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा गया है कि एसडीएम और एसीपी इस मामले की शिकायत की जांच करके अगली बैठक में पेश करें। तब तक यह शिकायत लंबित रहेगी। समाचारपत्रों ने उस बैठक की कार्यवाही को कवर भी किया था और इसी रूप में खबर भी प्रकाशित की गई थी। दोनों गुटों के पांच-पांच लोगों की कमेटी बनाने की दुष्यंत की घोषणा का शहर की पंजाबी बिरादरी में भी स्वागत हुआ था। इस स्वागत का नतीजा यह निकला कि कंवल खत्री गुट ने इसे अपनी हार मानी और अस्पताल का अवैध कब्जा हाथ से निकलने का डर सताने लगा। तब इस गुट की मदद के लिए राजनीतिक रसूख वाले लोग आए और पूरा एजेंडा और उसकी कार्यवाही ही बदलवा दी। पूरी कार्यवाही की वीडियो अगर दुष्यंत चौटाला ने मांग ली तो इसके साजिशकर्ता क्या जवाब देंगे। जांच हुई तो इसके दायरे में डीसी दफ्तर के क्लर्क और अफसर भी आयेंगे, जिनकी देखरेख में ग्रीवेन्स कमेटी की कार्यवाही रिपोर्ट तैयार की जाती है।

नाकारा विभागों की बदमाशी

ग्रीवेन्स कमेटी की लिखित कार्यवाही के साथ जिला रजिस्ट्रार सोसाइटीज की एक रिपोर्ट भी लगाई गई है। यह रिपोर्ट इस परिवाद के सिलसिले में कोई पढ़ेगा तो सिर पकड़ लेगा। पूरे परिवाद में दरअसल किसी और सोसाइटी के विवाद की रिपोर्ट लगा दी गई है। जिसमें तमाम गलत जानकारियां दी गई हैं। जिसमें बताया गया कि 9 जून 2016 को इस सोसाइटी का चुनाव हुआ, जबकि श्रीराम धर्मार्थ सोसाइटी का चुनाव 2016 में हुआ ही नहीं। इनमें जिन लोगों को पदाधिकारी बताया गया, उन नामों के लोग श्रीराम धर्मार्थ में कभी सदस्य थे ही नहीं। इसी तरह इसमें पूर्व अध्यक्ष के रूप में किसी संजय पुंज का जिक्र है, जबकि संजय पुंज नाम का कोई भी शख्स शुरू से अब तक कभी भी श्रीराम धर्मार्थ संस्था का प्रधान नहीं रहा। समझा जाता है कि यह गुड़गांव की किसी सोसाइटी का विवाद श्रीराम धर्मार्थ संस्था के विवाद में जिला रजिस्ट्रार दफ्तर ने जोड़ दिया है। लेकिन हैरानी होती है कि डीसी दफ्तर में बैठे बाबू और अधिकारी क्या करते हैं, जिन्होंने इस रिपोर्ट को पढ़े बिना ही लिखित कार्यवाही रिपोर्ट में शामिल कर लिया। ऐसा काम तो लोग नशा करने के बाद ही करते हैं, वरना इतनी भयंकर गलती डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में नहीं होती। यह गहन जांच का विषय है कि डिप्टी सीएम की बैठकों को फरीदाबाद जिला प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। डिप्टी सीएम जो आदेश देते हैं, उसे ठीक से लिखित में दर्ज नहीं किया जाता। टेक्नॉलजी के जमाने में ऐसी कार्यवाही बैठकें गोपनीय नहीं होती हैं। हर कोई वीडियो रेकॉर्डिंग करता है और सबूत मौजूद रहते हैं। तो आखिर डीसी दफ्तर में किस अधिकारी या नेता या विधायक के कहने पर यह फेरबदल या हेराफेरी की गई।

अवैध ओपीडी चला रहे हैं

जिला रजिस्ट्रार सोसाइटीज के प्रशासक ने कोविड सेंटर की आड़ में इस अस्पताल की सील खुलवाई थी। लेकिन श्रीराम धर्मार्थ सोसाइटी के 12 लाख खर्च करवाने के बाद उस प्रशासक का कहीं अता-पता नहीं है, जबकि कंवल खत्री गुट वहां कब्जा करके बैठ गया है। इन लोगों ने वहां अब अवैध तरीके से ओपीडी शुरू करवा दिया है और टेस्टिंग भी की जा रही है। प्रशासक ने कोविड सेंटर चलाने के लिए जो कमेटी बनाई थी, अब वो भी वैध नहीं रही क्योंकि प्रशासक का कार्यकाल बढ़ाया ही नहीं गया और ऐसे में उसके द्वारा बनाई गई कमेटी भी अपने आप भंग हो गई। लेकिन यह गुट अब रोजाना अस्पताल में आकर बैठ रहा है और अवैध रूप से उसका संचालन कर रहा है। जाहिर है कि यह सब बिना राजनीतिक रसूख नहीं हो सकता। सत्तारूढ़ दल की मदद से सारे अवैध काम को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है। शहर की पंजाबी बिरादरी में इससे गलत माहौल बन रहा है।

फरीदाबाद भाजपा दफ्तर किसके पैसे....

पेज एक का शेष

होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए चंडीगढ़ से फरीदाबाद हुडा दफ्तर के अफसरों पर जबरदस्त दबाव बनाया गया कि वे प्राइम लोकेशन पर भाजपा को प्लॉट दिलाएं।

भाजपा की चाकरी में जुटे मुंह लगे हुडा के कुछ अफसरों ने सेक्टर 15 के प्लॉट का उल्लेख भाजपा नेताओं से कर दिया। इसके बाद दबाव बनाकर नहरपार सेक्टर 78 में जिला भाजपा को मिले प्लॉट का आवंटन रद्द कराया गया और उसके बाद सेक्टर 15 में देने का फैसला किया गया। लेकिन यह प्लॉट हूडा सीधे दे नहीं सकता था, इसलिए इसका विज्ञापन निकाला गया। चूंकि प्लॉट सिर्फ भाजपा को ही मिलना था, इसलिए इस विज्ञापन को कभी कभार छपने वाले समाचारपत्रों में इस ढंग से इतना छोटा निकाला गया कि किसी की नजर ही न पड़े। लेकिन इस विज्ञापन की भनक कहीं से जननायक जनता (जेजेपी) को पड़ गई। उसने भी खानापूर्ति के लिए आवेदन कर दिया लेकिन प्लॉट पाने को उसने मुद्दा नहीं बनाया। अगर जेजेपी समेत सारे राजनीतिक दल इसे मुद्दा बना देते तो शायद हूडा को भाजपा के प्लॉट देने की प्रक्रिया रोकनी

पड़ती। हुडा ने जिस गोपनीय तरीके से नहरपार सेक्टर 78 में भाजपा को प्लॉट आवंटित किया था, वही गोपनीयता सेक्टर 15 वाले प्लॉट के मामले में भी बरती गई। लेकिन मजदूर मोर्चा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए जनता को इसके बारे में खबरों के जरिए बराबर सूचित किया।

भाजपा दफ्तर बनाने के नाम पर स्कैंडल

रोहतक और गुड़गांव में भाजपा का दफ्तर बनने को लेकर जब विवाद सामने आया तो इसके जरिए एक स्कैंडल भी सामने आया। रोहतक सेक्टर 5 में रेलवे ओवरब्रिज के साथ एक एकड़ जमीन पर खड़ा बीजेपी का दफ्तर शुरू से विवादों के केंद्र में रहा है। यह जमीन सारे नियमों को ताक पर रखकर दी गई। यह दफ्तर साढ़े छह मंजिला है। इसे नोएडा की कंपनी विवाम कॉन्ट्रैक्ट इंडिया प्रा. लि. ने बनाया था। लेकिन असली कहानी कुछ और है। मीडिया रपटों और विपक्ष के आरोपों के मुताबिक जिस कंपनी को देश के पहले एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाने का ठेका मिला है, उसी से रोहतक में भाजपा का दफ्तर बनाने की डील हुई थी। यानी ठेके के बदले उस कंपनी को रोहतक में भाजपा का दफ्तर बनवा कर देना था। रोहतक दफ्तर पर सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। भाजपा का रोहतक में दफ्तर बनवाने में पूर्व मंत्री और प्रमुख नेता मनीष ग्रोवर की मुख्य भूमिका रही है। इसी तरह गुडगांव में सबसे महंगी जमीन पर भाजपा का दफ्तर है। हुडा ने सबसे पहले 2017 में सेक्टर 41 में भाजपा को 4000 वर्गमीटर जगह आवंटित की। लेकिन भाजपा नेताओं को वह जगह पसंद नहीं आई। हालांकि इलाके के लोगों ने यह जगह आवंटित किए जाने का विरोध किया था। इसके बाद सेक्टर 30 में बेशकीमती जमीन भाजपा दफ्तर के लिए हूडा ने आवंटन की पेशकश की। एक तरफ तो भाजपा अपनी ही सरकार की मदद से हरियाणा के हर जिला मुख्यालय पर जमीन आवंटित करा रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब यही काम किया था तो भाजपा ने उसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया और अपनी ही सरकार की ओर से केस दर्ज करा दिया। कांग्रेस शासनकाल में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पंचकूला में कांग्रेस समर्थित अखबार नैशनल हेराल्ड और नवजीवन के लिए जमीन आवंटित की थी। हुड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कई अन्य नेता आज भी उस मामले में अदालत का सामना कर रहे हैं। एक अजीबोगरीब बात और भी है, वह यह कि भाजपा अपनी ही सरकार की मदद से अपने दफ्तर के लिए हर जिले में जमीन ले रही है लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी मुद्दा नहीं बनाया।

सहयोग के लिये

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. **प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।**
2. **रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन**
3. **एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।**
4. **जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207**
5. **राम खिलावन-बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने 9891164794**
6. **मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919**
7. **सुरेन्द्र बघेल - बस अड्डा होडल - 9991742421**

सोशल मीडिया पर गार्ड की तौहीन.....

पेज एक का शेष

एक शख्स ने एक मोटे पुलिस वाले का फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है - कोई मतलब नही था इस ट्वीट का, इस पुलिस वाले पर कौन पैसा लगाया? सरकार या जनता? जितेन्द्र भड़ाना नामक यूजर ने फरीदाबाद पुलिस द्वारा ही पोस्ट किए गए फोटो को पोस्ट करते हुए उस पुलिस वाले के शरीर पर घेरा बनाकर उसकी तोंद पर इशारा किया है। उसने यह भी लिखा है - फरीदाबाद पुलिस को चाहिए कि ऐसे फूले हुए टायरों में पंचर लगवा कर ही मार्किट में भेजे। अब इनको कोई सड़क पर चला दे तो सड़क को ही तोड़ेंगे ना। डबचिक....डबचिक...डबचिक।

पुलिस को छंगू हलवाई बताया

एक अन्य ट्विटर यूजर ने पीसीआर के साथ खड़े पुलिसकर्मी का फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है - उन पर बंदूक तान दे तो कुछ नहीं कर पाएगा। निहत्थे होते हैं वो। थोड़ा इस पापी पेट पर भी ध्यान दीजिए। क्लासी इंडियन का ट्वीट तो और भी कमाल का है-आप को खबर,, ओह माफ करना...पुलिस तो हमेशा देर से है आती है शायद ये सोच के आपने ये लेख लिखा है और एक 10 हजार माह कमाने वाले के पेट का मजाक बनाया है...आपको अपने आस पास पहले देखना चाहिये जो मोटी तनख्वाह भी ले रहे और छंगू हलवाई जैसा पेट लिए घूम रहे,, IndusindBank को आप मेल कर सकते हैं। एक यूजर ने लिखा है कि थानों और चौकियों में कोई भी जाकर देख सकता है कि वहां तैनात पुलिस वालों से ज्यादा फिट तो होम गार्ड वाले रहते हैं। यूजर गौरव चावला ने डीजीपी हरियाणा को टैग करते हुए लिखा है -Is it legal and OK to socially create awkward situation for someone on social media ? इसका हिन्दी में अर्थ यह है कि डीजीपी हरियाणा बताइए कि क्या सोशल मीडिया पर इस तरह किसी के लिए अटपटा लिखा कानूनी रूप से सही है। नवोदित भारत ने गौरव चावला के ट्वीट की तारीफ करते हुए लिखा है कि हमें अब इन्हें मॉरल पुलिसिंग सिखानी पड़ेगी। अभिजीत ने लिखा है-

This tweet is not in good sense. Kindly apologize. @cmohry @police_haryana Kindly look into this as it promotes body shaming and defames a person who is on his duty. इसका हिन्दी में मतलब यह हुआ कि फरीदाबाद पुलिस का यह ट्वीट समझ में ठीक नहीं है। कृपया माफी मांगे। सीएम हरियाणा और हरियाणा पुलिस को टैग करते हुए लिखा गया है कि कृपया इसे देखे। एक शख्स जो ड्यूटी कर रहा है कैसे उसके शरीर का मजाक उड़ाया जा रहा है।

पहली बार ऐसा नहीं हुआ

फरीदाबाद पुलिस की ऐसी बुरी ट्रोलिंग पहले भी हुई है। कई बार तो फरीदाबाद पुलिस साम्प्रदायिक ट्वीट भी करती है, जिसमें अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत साफ-साफ दिखती है। मात्र आरोपी बन जाने पर, अदालत से फैसला आये हुए बिना फरीदाबाद पुलिस उन पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें अपराधी करार दे देती है। मजदूर मोर्चा के पाठक पिछले अंकों में फरीदाबाद पुलिस के विवादास्पद ट्वीट के बारे में विस्तार से पढ़ चुकी है। उन खबरों के छपने के बाद पुलिस अधिकारियों ने गोदी मीडिया के अखबारों में छपवाया कि किस तरह फरीदाबाद पुलिस के ट्वीट की तारीफ हो रही है। लेकिन 21 जुलाई को जो ट्रोलिंग हुई है, सोशल मीडिया के इतिहास में फरीदाबाद पुलिस उन्हें याद रखेगी। मजदूर मोर्चा के पास सभी ट्वीट के स्क्रीन शॉट सुरक्षित हैं।

सूत्रों का कहना है कि फरीदाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल पहले बड़े स्तर का अधिकारी नहीं देखता था। पुलिस कमिश्नर के स्तर पर तो आज तक कभी भी फरीदाबाद पुलिस का ट्विटर हैंडल नहीं संभाला गया। हालांकि ओपी सिंह आईपीएस के नाम से उनका अपना अलग ट्विटर हैंडल है लेकिन उस पर ऐसी चीजें नहीं डाली जातीं। महत्वपूर्ण यह है कि फरीदाबाद पुलिस अपने गुड वर्क का प्रेस नोट इस ट्विटर हैंडल पर नहीं डालती, लेकिन फालतू की बातें डालती रहती है।